

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 07 मई, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित अवचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रु0 3,70,000/- (रुपये तीन लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-18

आयोजनेत्तर

(धनराशि रु0 हजार में)

2425-	सहकारिता	वर्तमान
001-	निदेशन तथा प्रशासन	स्वीकृति
05-	सहकारिता न्यायाधिकरण	
04-	यात्रा भत्ता	10
05-	स्थानान्तरण भत्ता	10
08-	कार्यालय व्यय	25
11-	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	150
18-	प्रकाशन	10
22-	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
29-	अनुरक्षण	10
44-	प्रशिक्षण व्यय	10
45-	अवकाश यात्रा व्यय	50
47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	25
	योग 05	370

(रु0 तीन लाख सत्तर हजार मात्र)

2- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउंचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6- इस सम्बन्ध वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर सूचित करें।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-सहकारिता न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8- ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या:-13/XXVII-(1)/2010 दिनांक 03 मई, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।

संख्या:-620 (1)/XIV-1/ 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसचिव।